IJARASEM

ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 10, Issue 4, July-August 2024

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 4, July-August 2024 |

राजस्थान में सुशासन: 2009 से 2018 तक की सरकारों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन

[1]DR. VIKAS KUMAR SHARMA & [2]RAJESH KUMAR MEENA

[1]ASSISTANT PROFESSOR IN POLITICAL SCIENCE, SPNKS GOVT. PG COLLEGE, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

[2]ASSISTANT PROFESSOR IN POLITICAL SCIENCE, SHAHEED CAPTAIN RIPUDAMAN SINGH GOVT. COLLEGE, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

सार

राजस्थान सरकार राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है । सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं निर्णयों को धरातल पर क्रियान्वित करने तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परिचय

सुशासन (Good governance) से तात्पर्य किसी सामाजिक-राजनीतिक ईकाई (जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि) को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अन्तर्गत बहुत सी चीजें आतीं हैं जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबन्धन, कानून का शासन, सदाचार इत्यादि। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या सम्पूर्ण अभाव, जंगल राज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि दुःशासन के लक्षण हैं।

'शासन' शब्द में 'सु' उपसर्ग लग जाने से 'सुशासन' शब्द का जन्म होता है। 'सु' उपसर्ग का अर्थ शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भाषा में सुशासन की तरह लगने वाले कुछ और बहुप्रचलित-घिसेपिटे शब्द हैं जैसे - प्रशासन, स्वशासन, अनुशासन आदि। इन सभी शब्दों का संबंध शासन से है। 'शासन' आदिमयुग की कबीलाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता के विकासक्रम में अलग-अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होती आई है। इस विकासक्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोककल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। इस अर्थ में शासन की सभी प्रणालियाँ कृत्रिम हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि सुशासन व्यक्ति को भ्रस्टाचार एवं लालफीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट S(simple)साधारण,M(moral)नैतिक,A(accountable)उत्तरदायी,R(responsible)जिम्मेदारियोग्य,T(transparent)पारदर्शी बनाता है ।[1,2,3]

बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई करने पर ज़ोर दिया।

सुशासन पर ज़ोर देना राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है।

राजस्थान सरकार राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं निर्णयों को क्रियान्वित करने तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

CM ने विकास भारत संकल्प यात्रा की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिये, मंडल में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित जनसुनवाई सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के लिये ज़िला मुख्यालय एवं राजधानी तक न आना पड़े।

राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों, खनन और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई

करने का निर्देश दिया गया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

यात्रा 15 नवंबर, 2017 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुई।

इसका उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है।

यात्रा के दौरान विवरण एकत्र करके इन योजनाओं के संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना।

यात्रा के माध्यम से जिन योजनाओं का प्रचार किया जाएगा उनमें आयुष्मान भारत PMJAY, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना शामिल हैं।

विशेष रूप से डिज़ाइन की गई पाँच IEC (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का संदेश देंगी।

25 जनवरी 2018 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने का लक्ष्य है।[4,5,6]

सुशासन केन्द्र (सीजीजी) की स्थापना और पंजीकरण 31 मार्च 2005 को संस्थान में एक सोसायटी के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के शासन सुधार कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में समन्वय और सहायता प्रदान करना था। इसके लिए, यह कार्रवाई अनुसंधान करता है, पेशेवर सलाह प्रदान करता है, और सरकारी विभागों और अन्य संबंधित एजेंसियों के लिए परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करता है। इस तरह, यह राज्य में सुधार पहलों को लागू करने के लिए नीति निर्माताओं, सिविल सेवकों और उद्योगों, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की जरूरतों को भी पूरा करता है। सीजीजी राज्य सरकार, इसके विभिन्न विभागों और अधिकारियों और स्थानीय स्वशासन और नागरिक समाज के लिए एक संसाधन और क्षमता निर्माण केंद्र है। सीजीजी का लक्ष्य राज्य की शासन प्रणाली में उत्कृष्टता लाना और इसे टिकाऊ बनाने के लिए नागरिक समाज की संस्थाओं को मजबूत करना है। सरकार और अन्य संगठनों पर कार्रवाई अनुसंधान अध्ययन आयोजित करके एक मजबूत ज्ञान-आधार बनाने, परिणामों में सुधार करने और संगठनों और व्यक्तियों के प्रदर्शन लेखा परीक्षा के लिए उपकरण और तकनीक विकसित करने और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विचार-विमर्श

राजस्थान गुड गवर्नेन्स के मामले में देश में पहले नंबर पर रहा है। प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की ओर से 'स्टेट ऑफ स्टेट्स का ॅन्क्लेव 2018' में राजस्थान को 'बेस्ट परफार्मिंग बिग स्टेट इन गर्वेनेन्स' घोषित किया गया है। दिल्ली में आयोजित का ॅन्क्लेव में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहलोत को यह अवार्ड दिया।

गवर्नेन्स के क्षेत्र में इस रैंकिंग के लिए विधायकों के आपराधिक रिका ॅर्ड, पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए अधिकारों के वितरण, नागरिकों और पंचायतों के लिए ई-सेवा जैसे कार्यों को आधार माना गया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान सुशासन के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी रहा है। राजस्थान ने देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून लागू किया।

राजस्थान की जनता को सुनवाई का अधिकार दिया है। गहलोत ने कहा कि मा ॅब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाया है। ऑनर किलिंग के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया है। जिससे लोगों के मर्जी से जीने के अधिकार और जाति या धर्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव को रोकने को मजबूती मिलेगी। इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।[7,8,9]

कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आम जन के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए प्रदेश में किये गए नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में किये जा रहे नवाचारों से सुशासन की दिशा में नए मार्ग

प्रशस्त हुए हैं।

इस अवसर पर एचसीएम रीपा के महानिदेशक नवीन महाजन ने कहा कि राजस्थान एवं देश के विभिन्न राज्यों के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया और अपने क्षेत्र में किये नवाचारों के अनुभव साझा किये। उन्होंने कहा कि इन अनुभवों से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक दूसरे से सीखने को मिला है।

चूरू जिले के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले में खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की गई, जिसका सीधा प्रभाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ा और उन्होंने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि चूरू जिले को खेलो इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक जितेंद्र कुमार सोनी ने नागौर जिले में सिलिकोसिस बीमारी से बचाव और इससे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए किए गए नवाचारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नागौर जिले में पत्थर की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को वैट ड्रिलिंग, मास्क के उपयोग और बचाव के अन्य उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया। अब पीड़ित को रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी सहायता के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर रुक्मणि रियार ने जिले में गंग नहर के जल वितरण तंत्र को कंप्यूटरीकृत करने के अपने ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे जल के असमान वितरण की शिकायतों में काफी हद तक कमी आई है। अब आमजन को नहर में छोड़े गए जल की मात्रा तथा वितरित जल की मात्रा की सूचना फोन एप पर मिल जाती है। इससे वितरण तंत्र पारदर्शी हुआ है और किसान हर रोज पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करना तय करता है।

उद्योग विभाग की विशिष्ट सचिव नेहा गिरी ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के आई स्टार्ट इनिशियेटिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स को अनुदान सहित अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीण युवाओं को भी स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नए बिजनेस आइडिया को सहारा देने के लिए शुरू से लेकर इंडस्ट्री खड़ी करने तक स्टेप-बाई-स्टेप मदद उपलब्ध कराई जा रही है।[10,11,12]

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शासन सचिव आनन्दी ने जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निराकरण के लिए शुरू किये गए जन सम्पर्क पोर्टल तथा 181 हैल्पलाइन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी फीडबैक तंत्र विकसित किया गया है।

बीकानेर के जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिलों में लोक शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक माह के निश्चित दिनों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर जन सुनवाई के माध्यम से आम जन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

परिणाम

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि वेद सुशासन के सिद्धांतों का खजाना हैं और इन सिद्धांतों को अपनाकर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार वैदिक शिक्षा के संरक्षण के लिए कार्य को आगे बढ़ाएगी तथा देववाणी संस्कृत के प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

गहलोत राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर 'लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन के लिए राष्ट्रीय वैदिक विमर्श' विषय पर आयोजित वर्चुअल वेद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने वैदिक धरोहर एवं पाण्डुलिपि शोध संस्थान, राजस्थान संस्कृत अकादमी पर आधारित पोर्टल तथा ''पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ'' के संदेश वाले पोस्टर का लोकार्पण किया।

उन्होंने एक बयान में कहा कि वेदों का जितना गहन अध्ययन किया जाएगा, सुशासन का संकल्प उतना ही मजबूत होगा।

स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने विश्व में वैदिक संस्कृति के महत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा मानवता एवं विश्व शांति के लिए उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और समय पर न्याय देने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है और हर व्यक्ति इस तंत्र को पसंद करता है। समय पर न्याय देने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत को आज कानून के राज के लिए जाना जाता है।"[13,14,15]

यह लोगों की धारणा, देश की धारणा और विश्व की धारणा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विश्वविद्यालय ने सही मार्ग पर कदम बढ़ाया है।"

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के साथ विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यह देखकर प्रसन्नता होती है कि कई डिग्रीधारक न्यायिक क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह बताता है कि विश्वविद्यालय सही दिशा में जा रहा है।"

विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "एक आम आदमी आशा के साथ आपके पास आता है। हम देखते हैं कि जब लोग पारिवारिक विवाद के साथ आते हैं तो वे किसी की नहीं सुनते, लेकिन वकील जहां भी कहता है, आंख मूंदकर हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि उनका उस वकील में विश्वास है। यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह विश्वास बार और बेंच दोनों पर बना रहना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस विश्वास को बनाए रखना हम सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है क्योंकि बदलते वातावरण में लोगों की जरूरतें, तरीके, प्रौद्योगिकी आदि लोगों और इस व्यवस्था को बदल रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "हमें यह निर्णय करना है कि बदलाव का मार्ग क्या होना चाहिए। क्या यह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आपका मार्ग सकारात्मक है तो आपका मार्ग ना केवल न्यायिक क्षेत्र में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उज्ज्वल होगा। यदि रास्ता नकारात्मक है तो तो यह ना तो आपके व्यक्तिगत हित में और ना ही समाज के हित में होगा।"

इस अवसर पर, भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमर पाल सिंह मौजूद थे।

राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि प्रदेश में विकास, सुरक्षा और सुशासन का कमल खिलाना है। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का बिगुल राजस्थान के लोगों ने फूंक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने ये बातें अपने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन नवलगढ़ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही। इससे पहले धनखड़ ने जिला झूंझनू राजस्थान में रायमाता गांगियासर में माता की पूजा व मंडावा में शिवालय में भगवान शिव जी की आराधना कर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय की कामना की। इस मौके पर हर्षणी कुल्हेरी, महामंत्री सुरजीत, महामंत्री योगेन्द्र मिश्रा, राजेश दहिया, पवन शर्मा, शुभकरण, भूपेन्द्र , मनीषा, पूनम, विकास भालौठिया सहित कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नवलगढ़ विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी कार्यकर्ताओं की टीम और यहां की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस विधायक की अवांछित गतिविधियों से पूरा का पूरा नवलगढ़ परेशान हैं। भाजपा की टीम कांग्रेस विधायक की पराजय के लिए संकल्पबद्ध है और इस बार नवलगढ़ से बीजेपी का प्रत्याशी ही निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा।

उल्लेखनीय है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने झूंझनू जिला की सातों विधानसभा सूरजगढ़, झूंझनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, पिलानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठकें की और विधानसभा चुनाव के निमित्त की गई तैयारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की नीतियां ही ठोस गारंटी है।[16,17,18]

मोदी सरकार सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। आज दुनिया भर में भारत की प्रगति और विकास की चर्चा हो रही है। गरीब, किसान, श्रमिक, दुकानदार, युवा, महिला, व्यापारी हर भारतीय का सपना पूरा करना प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को

हर साल छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं। वर्ष 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत लंबी छलांग लगाते हुए आज पांचवें पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। इन नौ सालों में भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों को पीछे छोड़ा है।

कौशल विकास, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश में उद्यम एवं उद्योग को प्रोत्साहन और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया है और आज हम सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है।

निष्कर्ष

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने, 2047 तक भारत को विकसित करने के मिशन पर काम कर रही है। भाजपा शासन में हर घर शौचालय, रसोई गैस, नल से जल पहुंच रहा है। भाजपा ने जो चुनावों में राजनीतिक वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम बहन-बेटियों को न्याय दिलाया है। कश्मीर से धारा 370 हटाई और आज अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन कानून लाकर माताओं, बहनों को लोक सभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत हक दिया है। [19]

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार सुशासन के निम्नलिखित आठ विशेषताएँ होतीं हैं-[1]

विधि का शासन (rule of law)

समानता एवं समावेशन (equity and inclusiveness)

भागीदारी (participation)

अनुक्रियता (responsiveness)

बहुमत/मतैक्य (consensus oriented)

प्रभावशीलता दक्षता (effectiveness and efficiency)

पारदर्शिता (transparency)

उत्तरदायित्व (accountability)

निष्पक्ष आकलन (fair assessment)[20]

संदर्भ

1. "सुशासन क्या है" . UNESCAP , 2009. 6 अप्रैल, 2018 को एक्सेसरीज़ किया गया।
2. ^ एबी खान 16
3. ^ एगेरे १
4. ^ एबी अगेरे 4
5. ^ एबीसी पोलुहा, ईवा; रोसेंडाहल, मोना (2002)। 'अच्छे' शासन का विरोध: प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और सार्वजनिक स्थान पर क्रॉसकल्चरल दृष्टिकोण । रूटलेज।आईएसबीएन 978-0-7007-1494-0.
6. ↑ फुकुयामा, फ्रांसिस (जनवरी 2013). "शासन क्या है?". विकास केंद्र . कार्य पत्र 314.
7. ↑ रोटबर्ग, रॉबर्ट (जुलाई 2014). "सुशासन का अर्थ है प्रदर्शन और परिणाम". शासन . 27 (3): 511–518. डोई : 10.1111/gove.12084 .
8. ↑ ग्रिंडल, मेरिली (अक्टूबर 2004) "अच्छा पर्याप्त शासन: विकासशील देशों में गरीबी में कमी और सुधार". शासन . 17 (4): 525–48. डोई : 10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x .

9. ^ लॉसन, रॉबर्ट (2012)। "बुक रिव्यू ऑफ़ बो रोथस्टीन: द लेज़ ऑफ़ गवर्नमेंट: करप्शन, सोशल ट्रस्ट, एंड इनक्लिलिटी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव". सार्वजनिक चॉइस . 150 (3–4): 793–795. डोई : 10.1007/s11127-011-9903-y . एस2सीआईडी 153403374 .
10. ^ रोथस्टीन, बीओ (2011)। सरकार की गुणवत्ता: भ्रष्टाचार, सामाजिक विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में असमानता । शिकागो: शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. ^ "विश्व विकास कंपनियों को एशिया की ओर खींचता है। वे अपने सत्तावादी शासन को क्या संभाल सकते हैं?" . एचबीएस वर्किंग नॉलेज . 28 नवंबर, 2018.
12. ^ रोथस्टीन, बी.ओ.; टेओरेल, जान (2008)। "सरकार की गुणवत्ता क्या है? निष्पक्ष सरकारी देखभाल का एक सिद्धांत" शासन . 21 (2): 165–190. डोई : 10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x . आईएसएसएन 0952-1895 .
13. ↑ इटन, टिम वी., और माइकल डी. एकर्स। "व्हिसलब्लोइंग और सुशासन". सीपीए जर्नल 77, नंबर 6 (जून 2007): 66–71। बिजनेस सोर्स कम्प्लीट , ईबीएससीओ होस्ट (22 मार्च, 2016 को एक्सेसरीज़ किया गया)।
14. ^ [ए बी] अगेरे १०
15. ^ अगले 11
16. ^ [a b c] "अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आईएमएफ का दृष्टिकोण - एक उत्कृष्टता" । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 20 जून, 2005। 2 नवंबर 2009 को अपलोड किया गया ।
17. ^ "शासन और विकास" (पीडीएफ) . विश्व बैंक . 1992. . 0-8213-2094-7.
18. ↑ कॉफ़मैन, डैनियल और क्राय, आर्ट, "शासन के बिना विकास" (नवंबर 2002)। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र संख्या 2928।
19. ^ एगेरे 2
20. ↑ "आईएमईएफ और सुशासन" , आईएमएफ. 12 अगस्त 2009 को पुनः प्रकाशित।

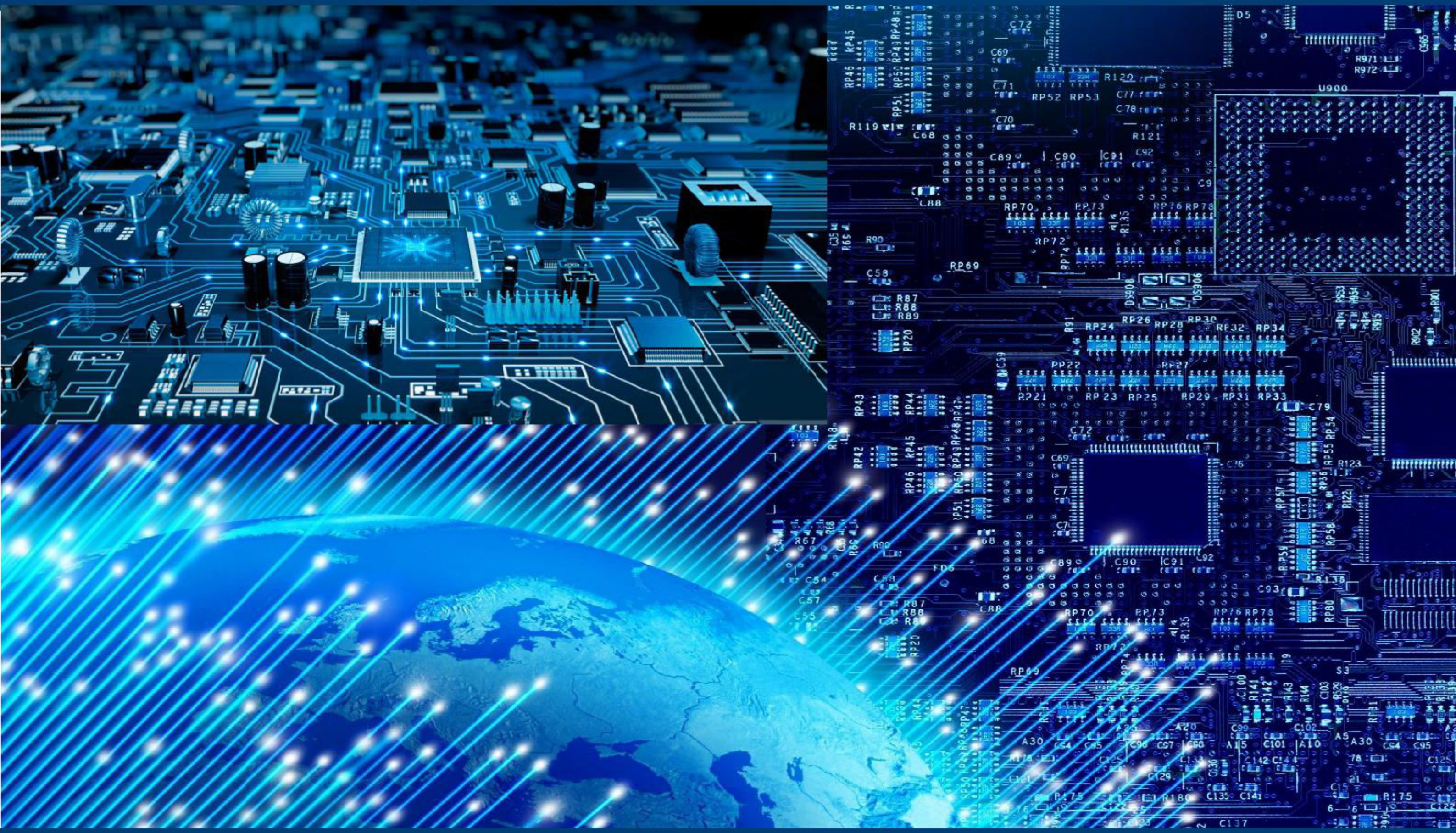

IJARASEM

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

निस्केयर
NISCAIR

International Journal of Advanced Research in
Arts, Science, Engineering & Management
(IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com